

भाजपा कार्यकर्ता बिना स्वार्थ के राष्ट्र सेवा के लिए काम करता है- भजनलाल

पार्टी किसी एक व्यक्ति या परिवार की नहीं, पुराने अनुभव के साथ नया जोश जरूरी है- बी.एल. संतोष



जयपुर में कॉन्स्टिच्यूशन क्लब में आयोजित हुई भाजपा की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

जयपुर, 3 जनवरी । भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जयपुर में आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन सत्र को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तथा भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने संबोधित किया। इस दौरान भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉ. अलका गुर्जर,

■ **भाजपा की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि संगठनात्मक कार्यशाला का उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को मूल्यों, आदर्शों व जन सेवा से जोड़ना है।**

राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पुनिया तथा अशोक परनामी सहित, पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए बीएल संतोष ने कहा कि पार्टी किसी एक व्यक्ति और परिवार की नहीं है। नए लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए नए लोगों के आने से पार्टी में नयापन आता है। उन्होंने कहा

कार्यशाला भाजपा के संगठन को प्रदेश, जिला, मंडल और बुथ तक सक्रियता से मजबूत करने के साथ ही, केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रिकार्ड बनाते हुए ३१ दिसम्बर तक 3५ हजार मेगावाट का आंकड़ा पार कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मोडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संगठनात्मक कार्यशाला का उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को मूल्यों, आदर्शों और जनसेवा के भाव से जोड़ना है। भाजपा की राजनीति सेवा भाव पर आधारित है। हम सब राजनीति में सेवक के रूप में आए हैं और जनसेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करना हमारा लक्ष्य है।

भाजपा कार्यकर्ताओं की यह

बांग्लादेश के क्रिकेटर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
बनाकर अभियान चला रही है। वह सड़क किनारे छोटी-छोटी सभाएँ कर रही है और तृणमूल कांग्रेस सरकार की नाकामी और चोट पाने के लिए मुसलमानों को खुश करने की उसकी नीति को उजागर कर रही है। इसी दौरान, बंगाल के इस हिस्से में भी मुस्लिम समुदाय की माँग बढ़ती जा रही है और यहाँ भी अत्याचार की घटनाएँ सामने आ रही हैं। इस क्षेत्र में लगातार साम्प्रदायिक झड़पें हो रही हैं और कुछ मामलों में हिंदुओं पर हमले हुए हैं। राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में दिनदहाड़े एक पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में आरोपियों को न तो गिरफ्तार किया गया और न ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कई अन्य मामलों में राज्य पुलिस ने मुसलमान आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने से भी इनकार किया है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इन लगातार अत्याचारों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। ममता ने हिंदुओं को इन भयानक हत्याओं

का मुद्दा भी नहीं उठाया है। राज्य भाजपा इन सभी मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है और ममता सरकार पर इन जघन्य घटनाओं पर चुप रहने का आरोप लगा रही है। माना जा रहा है कि लोग इन घटनाओं पर चुपचाप ध्यान दे रहे हैं और आने वाले चुनावों में इसका असर दिखाई दे सकता है।

जब गडकरी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
चुके हैं। इसके बाद नितिन गडकरी ने अपनी शादी की तारीख भी सही-सही याद कर ली। बातचीत में दिलीप ने गडकरी से अपने गाँव में “एक छोटी सी सड़क” बनवाने की गुजारिश की। फराह ने मजाक करते हुए कहा कि सड़क को सोधे दिलीप के घर के बीच से ही निकाल सकते हैं। इस पर कंचन गडकरी ने बताया कि उनके अपने पिता के साथ ऐसा हो चुका है, जब सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए उनका घर ही तोड़ दिया गया था।

तृणमूल सांसद मौसम नूर कांग्रेस में शामिल

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद मौसम नूर शनिवार को फिर कांग्रेस में शामिल हो गयीं, जिसे पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव से पहले वहां सत्तारूढ़ दल को झटका माना जा रहा है। मौसम नूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत ए.बी.ए. गनी खान चौधरी की भतीजी हैं।

श्रीमती नूर ने राजधानी में कांग्रेस के मुख्यालय पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ली। उन्होंने राज्य सभा से इस्तीफा देने की भी घोषणा की है। मातदा लोक सभा सीट से 1६वीं और 1७वीं लोकसभा में कांग्रेस के टिकट पर जीती मौसम नूर 20१९ में तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गयी थीं। उन्हें तृणमूल कांग्रेस ने अप्रैल २०२० में कांग्रेस में भेजा था। उनका राज्य सभा का कार्यकाल आगमी अप्रैल में समाप्त हो रहा था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना

■ **मौसम नूर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिवंगत एबीए गनी खान चौधरी की भतीजी हैं।**

इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष भेज दिया है। नूर ने कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश, पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार तथा लोकसभा सांसद ईशा खान चौधरी की मौजूदगी में पुनः कांग्रेस की सदस्यता ली। इस मौके पर उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने पुनः कांग्रेस के साथ जुड़ कर दिवंगत ए.बी.ए. गनी खान चौधरी (पूर्व केंद्रीय मंत्री) की विरासत को मजबूत करने का निर्णय लिया है।

अमेरिका ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
शहर के कुछ हिस्सों से काले धुएं के गुबार उठते देखे। धमाके और विमानों को लागूभ ९० मिनट तक देखा गया। एसोसिएटेड प्रैस द्वारा सत्यापित वीडियो में कैराकस और एक अनजान तटीय शहर के ऊपर रात में आकाश में धुएं के गुबार साथ बार-बार मूक धमाके देखे गए, जो आपसपास की पहाड़ियों को रोशन कर रही थे। अन्य फुटेज में कारों राजमार्गों पर चलती हुई दिखाई दीं, जबकि उनके पीछे तेज धमाकों की रोशनी दिख रही थी। फैंडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेज़ुएला के हवाई क्षेत्र और नजदीकी क्यूरासाओ में अमेरिकी वाणिज्यिक और निजी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया, यह कहते हुए कि “चल रही सैन्य गतिविधियों से जुड़ी उड़ानें सुरक्षा जोखिम” हैं। ट्रंप की घोषणा के बावजूद, वाइट हाउस या पेंटागन से तुरंत कोई विस्तृत ब्रीफिंग नहीं आई। पेंटागन ने प्रश्नों का जवाब वाइट हाउस को दिया, जबकि अमेरिकी दक्षिणी कमांड ने प्रतिक्रिया नहीं दी। ट्रंप फ्लोरिडा के अपने निजी क्लब में थे और सोशल मीडिया पर अपनी प्रारंभिक पोस्ट के बाद उन्होंने कोई और टिप्पणी नहीं दी। रॉयटर्स ने बाद में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेज़ुएला के अंदर

हमले किए, हालांकि लक्ष्यों या उद्देश्यों के बारे में विवरण नहीं दिया गया। ट्रंप प्रशासन मादुरो पर 5 माह से दबाव बढ़ा रहा था, मादुरो पर अमेरिका ने नार्को आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। अगस्त से, वॉशिंगटन ने वेनेज़ुएला के उत्तरी तट के पास एक बड़े बेस के निर्माण का आदेश दिया, जिसमें एक विमान वाहक पोत, युद्धपोत और उन्नत लड़ाकू जेट्स शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य उपस्थिति है।

सितंबर की शुरुआत से, अमेरिकी सैन्य बल कैरेबियाई सागर और पूर्वी प्रशांत में नौकाओं पर हमले कर रहा है, उसका आरोप था कि इनमें नशीले पदार्थ हैं। अमेरिका ने डेटा जारी कर ३५ नावों पर हमलों और कम से कम 1१५ लोगों की मौत की सूचना दी थी। ट्रंप ने इन अभियानों को यूएस में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक बताया और कहा कि वॉशिंगटन डूंग कार्टेल्स के खिलाफ “सशस्त्र संघर्ष” में जुटा है।

पिछले सप्ताह, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला के एक ऐसे क्षेत्र पर हमला किया था, जहां नौकाओं में नशीले पदार्थ लदे हुए थे। वर्तमान दबाव अभियान के दौरान वेनेज़ुएला की ज़मीन पर की गई यह पहली स्थल सैन्य

कार्रवाई थी। अन्य मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है कि इन ऑपरेशन्स के पीछे सीआईए थी। सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ, वॉशिंगटन ने प्रतिबंधों का भी विस्तार किया है। प्रतिबंधित तेल टैंकरों को ज़ब्त किया है और कहा कि ट्रंप ने वेनेज़ुएला के तेल पर जो रोक लगाई है, वह काराकस पर आर्थिक दबाव को कड़ा करने के उद्देश्य से उठाए गए कदम हैं। रॉयटर्स के अनुसार, ट्रंप ने बार-बार ज़मीन पर हमलों की धमकी दी है और निजी तौर पर मादुरो से देश छोड़ने का आग्रह किया है। इस सप्ताह के शुरू में, उन्होंने कहा कि मादुरो के लिए यह “समझदारी” होगी कि वे सत्ता से हट जाएं।

वेनेज़ुएला ने अमेरिकी “सैन्य आक्रमण” को नकारते हुए, वॉशिंगटन पर देश के तेल और खनिज संसाधनों को हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सरकार ने कहा कि अमेरिका “सफल नहीं होगा” इन संसाधनों को लेने में, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की निंदा करने की अपील की।

एक बयान में, सरकार ने कहा कि मादुरो ने “सभी राष्ट्रीय रक्षा योजनाओं को लागू करने का आदेश दिया है” और “बाहरी संकट की स्थिति” घोषित की है, जिससे अधिकारियों को विस्तारित आपातकालीन शक्तियाँ और सशस्त्र

बलों को एक बड़ी भूमिका मिलेगी। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्टावो पेट्रो ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैराकस पर बमबारी की जा रही है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकाल बैठक का आान किया। बाद में उन्होंने वह सूची प्रकाशित की, जिसमें बमबारी की गई साइटों का उल्लेख किया गया है, इनमें कैराकस में क्यूपर्टेल दे ला मोंटाना बैक भी शामिल था, जो बूहगो चावेज का मकबरा है, जो चैविज़्मो के राजनीतिक आंदोलन 1९९९ से वेनेज़ुएला पर शासन कर रहा है।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमलों की निंदा की, और ईरानी राज्य टेलीविजन ने कैराकस में धमाकों के दृश्य प्रसारित किए। क्यूबा, जो मादुरो का करीबी सहयोगी और अमेरिका का दीर्घकालिक विरोधी है, ने भी हमले की निंदा की। जैसे-जैसे स्थिति स्पष्ट होती है, शनिवार की सुबह की घटनाएँ न सिर्फ वेनेज़ुएला की आंतरिक राजनीति को फिर से आकार देने की संभावना रखती हैं, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और लैटिन अमेरिका में अमेरिकी संबंधों को भी प्रभावित कर सकती हैं।

ट्रंप ने एक फोटो भी जारी किया, जिसमें मादुरो की आंखों पर पट्टी बंधी हुई दिख रही थी।

मजनू का टीला के कैफे खतरे में

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 3 जनवरी। आईएसबीटी के पास स्थित दिल्ली का मजनू का टीला, अपने सस्ते तिब्बती और एशियाई खाने वाले कैफे के लिए कॉलेज छात्रों में बहुत लोकप्रिय है, परंतु अब यहाँ के कई ‘फूड कोर्ट’ व कैफे बंद हो सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में अधिकारियों को

■ **दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, स्वीकृत बिल्डिंग प्लान व पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना जो कैफे चल रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए।**

निर्देश दिया कि वे उन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो मंजूरशुदा बिल्डिंग प्लान और पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के बिना चल रहे हैं।

बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि वे इलाके के कई कैफे, बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ उचित कार्रवाई करें, जो सही फायर सेफ्टी व्यवस्था के बिना अवैध रूप से काम कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेलाल की पीठ ने उस याचिका का निपटारा किया, जिसमें कहा गया था कि यमुना नदी के किनारे स्थित मजनू का टीला में कई अनाधिकृत रेस्टोरेंट बहुमंजिला इमारतों में बिना जरूरी कानूनी मंजूरी के चल रहे हैं। अदालत ने यह भी नोट किया कि इस मामले में डीडीए पहले ही स्वतः संज्ञान लेकर शिकायत दर्ज कर चुका है।

पूर्वोत्तर छात्रों की सुरक्षा के लिए गठित बेजबरूआ कमेटी की सिफारिशें फिर चर्चा में

देहरादून में एमबीए छात्र एंजल चकमा के नस्लीय उत्पीड़न के बाद हत्या करने से इस समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग की जा रही है

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। देहरादून में त्रिपुरा के एमबीए छात्र एंजल चकमा की हाल ही में कथित नस्लीय हमले में हुई हत्या के बाद, एक समिति की 1० साल पुरानी रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें फिर से चर्चा में हैं, जिन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है।

2०१४ में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुख्यात नीडो तानियम हत्याकांड के बाद गृह मंत्रालय ने पूर्व आईएसएस अधिकारी एमपी बेजबरूआ की अध्यक्षता में बेजबरूआ समिति गठित की थी। इसका उद्देश्य था कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को महानगरों और अन्य शहरों में जिन चिंताओं, भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है, उसकी जांच की जाए और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के उपाय सुझाये जाएं।

बेजबरूआ समिति ने हालांकि नीति स्तर पर उठाये जाने वाले निवारक और दंडात्मक कदमों के साथ विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी और गृह मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए निगरानी समिति बनायी है, लेकिन अब तक कार्रवाई अपर्याप्त रही है।

बेजबरूआ ने कहा, “हमने विभिन्न शहरों में बड़े पैमाने पर लोगों से बात करने के बाद कई सिफारिशें दी थीं। ये

■ **इस समिति का गठन 201४ से किया गया था जब दिल्ली में पूर्वोत्तर भारत के एक छात्र की हत्या कर दी गई थी।**

सिफारिशें निवारक और दंडात्मक दोनों तरह की हैं।”

पूर्वोत्तर क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से अलग तरह का मानते हुए बेजबरूआ ने कहा कि जो छात्र और लोग शिक्षा, काम आदि के लिए अन्य महानगरों में जाते हैं, उन्हें नस्लीय प्रकृति के अप्रिय अनुभवों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पुलों का निर्माण रिपोर्ट का मुख्य विषय था।

जब सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में पूछा गया तो बेजबरूआ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ कदम उठाये गये हैं, जैसे एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर (1०९३), पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए अलग छात्रावास, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में ज्यादा कुछ नहीं किया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों में से एक थी, नस्लीय प्रकृति की घटनाओं से निपटने के लिए कुछ क्षेत्रों के लोगों के

लिए आईपीसी और सीआरपीसी में विशेष प्रावधान शामिल करना। लेकिन, उस महत्वपूर्ण सिफारिश को 2०२४ के इन कानूनों में तीन नये नियमों—बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए में संशोधन के समय भी अनदेखा कर दिया गया है।

आईपीसी 1५३ (ए) और (बी) में नस्लीय भेदभाव और दुर्व्यवहार के गंभीर मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थे, निगरानी समिति ने कानून को और सख्त बनाने के लिए संशोधन के समय एक नया प्रावधान 1५३ (सी) जोड़ने का गृह मंत्रालय को प्रस्ताव दिया।

हालांकि, कानून बनाने वालों ने उस सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया, यह बात निगरानी समिति के एक सदस्य ने कही।

बेजबरूआ समिति और उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए गठित निगरानी समिति की सदस्य अलाना गोलमेई ने कहा, हमने पूर्वोत्तर के लोगों के लिए किसी अलग कानून की मांग नहीं की थी।उन्होंने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को जब वे अन्य जगहों पर पढ़ाई या काम के लिए जाते हैं, तो समान भेदभाव का सामना करना पड़ता है।”

महात्मा बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया प्र.मंत्री मोदी ने

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि महात्मा बुद्ध से जुड़े जो भी स्थल हैं, उनका संरक्षण और विकास करना परहेले ही स्वतः प्राथमिकता है। वे महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के यहां आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मोदी ने कहा कि सवा सौ साल के इंतजार के बाद महात्मा बुद्ध से जुड़ी भारतीय धरोहर और विरासत वापस लौटी है और अब भारतीय जनमानस

■ **मोदी ने कहा उन्हें खुशी है कि उनके नए साल के पहले कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा बुद्ध के कार्यक्रम से हो रही है।**

इन पवित्र अवशेषों का दर्शन करके कदा आशीर्वाद पा सकेगा। उन्होंने कहा कि 2०२६ की शुरुआत में ही यह उनके लिए बहुत प्रेरणादायक अवसर है कि उनके पहले सार्वजनिक कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बुद्ध के चरणों से हो रही है।

प्रधानमंत्री जिस प्रदर्शनी का

मनरेगा पर कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) के पक्ष में देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगी। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में मनरेगा बचाओ अभियान की रूपरेखा तैयार की गई थी।

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ८ जनवरी से सभी प्रदेशों में, बड़ी बैठक की जाएगी, जिसमें प्रदेश के सारे बड़े नेता और प्रभारी मौजूद होंगे। इस बैठक में सभी जिलों के काम का दाखिल दिया जाएगा, 1० जनवरी को सभी जिलों में

■ **कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी ४५ दिन का कार्यक्रम करेगी, जिसकी शुरुआत ८ जनवरी से होगी।**

प्रेस कॉन्फ्रेंस की जायेगी। इसमें पंचायती

राज को खत्म करने की साजिश को उजागर किया जाएगा।

११ जनवरी को सभी जिलों में , महात्मा गांधी जी या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने एक दिन का उपवास किया जाएगा। 12 जनवरी से २९ जनवरी तक हर पंचायत में चौपाल लगाई जायेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से सभी ग्राम प्रधानों

को पत्र लिखा जाएगा।

३० जनवरी को वार्ड और ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम किया जाएगा। ३१ जनवरी से ६ फरवरी के बीच डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के बाहर धारण दिया जाएगा। 7 फरवरी से 1५ के बीच विधानसभा और राज्यभवन का घेराव कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। 1६ फरवरी से 2५ फरवरी के बीच कांग्रेस पार्टी बड़ी रैली करेगी।

‘देशभर में फॉरेंसिक लैब का जाल बिछाया जाएगा’

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि इस पर 30 हजार करोड़ रु. की लागत आएगी

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में देशभर में फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का जाल बिछाया जायेगा, जिसपर 3० हजार करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2०२९ तक देश के हर राज्य में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय या केन्द्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला बनायी जायेगी।

शाह ने शनिवार को अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के विजयपुरम में मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का विषय संसदुल फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला था।

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बंडी संजय कुमार, संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य, गृह

■ **सरकार का विज़न है कि अपराधिक मामलों में त्वरित न्याय मिले।**

सचिव, विश्वविद्यालय के कुलपति और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 2०१९ से लेकर अब तक संसदीय परामर्शदात्री समिति की १२ बैठकें की हैं, जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का विज़न है कि अपराधिक कानूनों के पूरी तरह लागू होने के बाद समय पर न्याय मिले।

उन्होंने कहा कि सरकार 2०२९ तक ऐसी व्यवस्था बनायेगी, जिसमें तीन साल की अवधि में प्राथमिकी से लेकर उच्चतम न्यायालय तक न्याय की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सकेगी। उन्होंने कहा कि 2०२२ से अब तक हुए सुधार इसी

दिशा में किए गए प्रयास हैं। गृह मंत्रालय इन प्रयासों की व्यापक निगरानी कर रहा है और कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि न्याय देने की प्रक्रिया के लिए फॉरेंसिक क्षमताओं में बढ़ोतरी और विस्तार के लिए सरकार ने 20२० से ही फॉरेंसिक्स पर क्या केन्द्रीत करके काम किया। उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिताएं पिछले वर्ष जुलाई से अमल में हैं परंतु फॉरेंसिक्स की दृष्टि से इसे लागू करने का काम 2०2० से ही शुरू कर दिया था, जिसके सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं।

शाह ने कहा कि पहले देश के सामने पांच चुनौतियाँ थीं, जिनमें फॉरेंसिक जांच में प्रौद्योगिकी की कमी,

दिल्ली में 72 उड़ानें रद्द हुईं

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को खराब मौसम के कारण ७२ उड़ानें रद्द रहें और ३०० से अधिक उड़ानों की आवाजाही में देरी हुई। दिल्ली में आज सुबह कोहरा नहीं था, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में कोहरे के कारण दूर से आने वाली और वहां जाने वाली उड़ानें रद्द रही।

हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विमान सेवा कंपनियों ने आज दिल्ली आने वाली ३४ और यहां से जाने वाली 3८ उड़ानें रद्द कीं।

इसके अलावा 3०० से अधिक उड़ानों में देरी की भी सूचना है। उल्लेखनीय है कि आज दिल्ली में रनवे पर दूरश्या ठीक रही, लेकिन दूसरे शहरों में कोहरा रहा।